वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) चीनी उद्योग में अवैध आय की उत्पत्ति के बारे में राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा किए जा रहे विस्तृत अध्ययन का इन्तजार किया जा रहा है । संस्थान की रिपोर्ट में किए गए प्रस्तावों पर सरकार की प्रतिक्रिया, सार्वजनिक बहस के समाप्त होने और सुझावों के मिलने के बाद ही दीर्घकालीन वित्तीय नीति में अभिव्यक्त की जायेगी ।

राज्यों को ओवर-ड्राफ्ट भुगतान

1871. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके संबंध में मार्च, अप्रैल, 1985 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओवर ड्राफ्ट भुगतानों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक और महालेखाकार की भूलों के कारण कुछ दूसरे राज्यों के भुगतानों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) रिजर्व बैंक और महालेखाकार की इस भूल के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी भूलें नहीं हों, क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा एक राज्य विशेष को स्वीकृत एक बड़ी धनराशि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गलती से किसी दूसरे राज्य के खाते में हस्तांतरित कर दिया गया था, यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) भारत सरकार ने राज्यों को सलाह दी थी कि यदि वे निरन्तर सात कार्य दिवसों से अधिक के लिए 28-1-85 के अपने ओवर-ड्राफ्ट की सीमाओं से अधिक ओवर-ड्राफ्ट में रहते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक उनके भुगतानों को बंद कर देगा । उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश ने क्रमशः फरवरी और अप्रैल; 1985 में इन स्तरों को पार कर लिया था और प्रत्येक के भुगतान एक दिन के लिए रोक दिए गए।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने और किसी राज्य का भुगतान बंद नहीं किया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

खाद्यान्नों के भंडारण के लिए बैंक ऋण

1872. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 27 जून, 1985 को "दि टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि लगभग 3 करोड़ मीटरी टन खाद्यानों के भण्डारण के लिए लगभग 8 हजार करोड़ रुपए के बैंक ऋण की धनराशि अंतर्ग्रस्त है जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंच रहा है; और

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी हां ।

गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों अर्थात् भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों/उनकी एजेंसियों के